

बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद का 194वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

27 फरवरी 2020

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह] .

Total Short Notice Question- 10

पुनरीक्षित पेंशन का लाभ

*23 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

Will the वित्त विभाग be pleased to state:-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य में लगभग 4.50 लाख पुराने पेंशनभोगी कर्मी हैं और इनमें करीब दो लाख सेवानिवृत्त कर्मियों को ही पुनरीक्षित पेंशन का लाभ मिल रहा है तथा ढ़ाई लाख पेंशनभोगियों का पुनरीक्षण कार्य नहीं होने से उन्हें पेंशन वृद्धि का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे वंचित पेंशनभोगियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2017 में ही पेंशन पुरीक्षण का निर्णय हुआ था, किन्तु विभाग द्वारा लापरवाही बरतने के कारण शेष पेंशनभोगियों को पेंशन वृद्धि के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाकर शेष ढ़ाई लाख पेंशनभोगियों को पुरीक्षित पेंशन का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

*24 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

Will the परिवहन be pleased to state:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2018 में 9600 सड़क दुर्घटना से 6729 लोगों की मौत के मुकाबले वर्ष 2019 में 9979 सड़क दुर्घटना से 7155 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार सड़क दुर्घटना की संख्या में 7.07 प्रतिशत तथा मरने वालों की संख्या में 6.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सड़क दुर्घटना तथा इससे मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि का क्या कारण है ?

योजना का लाभ

*25 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):

Will the परिवहन be pleased to state:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए प्रत्येक पंचायत में पांच लोगों को वाहन खरीदने के लिए 50 फीसद या अधिकतम एक लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान किया है ;

(ख) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला में 1170 लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया, मात्र 180 लोगों को लाभ मिला है ;

(ग) क्या यह सही है कि जिला को 1 करोड़ 65 लाख 25 हजार 819 रुपये मिले, अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई माह से बेरोजगार युवकों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला की सभी पंचायतों में पांच-पांच लोगों को उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

घटनाओं की रोकथाम

*26 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

Will the गृह be pleased to state:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के भोरे स्थित प्रखंड में लगातार अपराध की घटनाएं अत्यधिक हो रही हैं, जिससे प्रखंडवासी भयभीत एवं आतंकित रहते हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतलाएगी कि वर्णित प्रखंड में हो रही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कार्रवाई करने का विचार कर रही है, यदि नहीं तो क्यों ?

बैंकों से कर्ज

*27 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

Will the वित्त विभाग be pleased to state:-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जीविका के तहत चलनेवाली स्वयं सहायता समूह है ;

(ख) क्या यह सही है कि एस.एस.जी. को बिहार के 17 पिछड़े जिलों में 6 से 7 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता है शेष 21 जिलों से 10 से 12 प्रतिशत के सामान्य ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता है ;

(ग) क्या यह सही है कि जीविका समूह चलनेवाली स्वयं सहायता समूह (एस.एस.जी.) की कर्ज सीमा को तीन से 10 लाख तक साथ, ही बैंकों के माध्यम से समूह के सभी सदस्यों को 10 हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा, सभी जिलों में इस समूह के सदस्यों को 6 से 7 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने का वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्ताव है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वयं सहायता समूह को 7 प्रतिशत पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना चाहती है ?

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

*28 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):

Will the योजना एवं विकास be pleased to state:-

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधान पार्षदों और

विधायकों के द्वारा वर्ष 2016-17 में 551 करोड़, वर्ष 2017-18 में 486 करोड़, वर्ष 2018-19 में 616 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सिफारिश की गई थी ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना में तमाम विकास गतिविधियां स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंताओं के माध्यम से संचालित होती हैं ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त योजना में तीन साल में कुल 1653 करोड़ रुपये दिए गए, जिसमें 907 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण-पत्र इंजीनियरों के द्वारा विभाग को दिया गया है, लेकिन 746 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को नहीं दिया गया है ;

(घ) क्या यह सही है कि पैसे लेने के बाद भी खर्च का हिसाब अधिकारी नहीं देते हैं ;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना में खर्च किये गए पैसे का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देनेवाले अधिकारियों / इंजीनियरों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

डाक बंगला का रखरखाव

*29 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक) :

Will the **जल संसाधन** be pleased to state:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के भोरे में गंडक सिंचाई परियोजना का शिविर कार्यालय है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त शिविर में एक डाकबंगला भी है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य अधिकारी ठहरते हैं और उनकी बैठकें भी होती हैं ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त डाकबंगले में खानसामा, माली, गार्ड तथा अन्य कर्मियों का अभाव है और मात्र एक कर्मी पांच हजार रुपये के मानदेय पर नियुक्त है, जिससे डाकबंगले के सौन्दर्यीकरण और रखरखाव में भारी कमी है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतलाएगी कि शिविर कार्यालय और डाकबंगले के रखरखाव, सौन्दर्यीकरण आदि को सुव्यवस्थित कब तक करना चाहती है ?

विशेष सुरक्षा का मापदंड क्या

*30 श्री मनोज यादव (भागलपुर, बाँका स्थानीय प्राधिकार) :

Will the गृह be pleased to state:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के राजनेताओं एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि इन नेताओं एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को उनके संबंधित जिले के आरक्षी अधीक्षक की अनुशंसा एवं अनुमति द्वारा यह विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाएगी कि राज्य के नेताओं एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने का क्या मापदंड है, किन-किन राजनेताओं एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को विशेष सुरक्षा मुहैया करायी गयी है ?

सुचारु आवागमन कबतक

*31 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):

Will the परिवहन be pleased to state:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी एवं पूर्वी चम्पारण तथा शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं अन्य जिलों से राजधानी पटना आनेवाले वाहन मुजफ्फरपुर से होकर आते हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर के दरभंगा मोड़ से बैरिया तक फोरलेन सड़क पर दो लेन बाई एवं दाई तरफ मरम्मती कार्य के कारण परमानेन्ट बड़े-बड़े मालवाहक वाहन खड़े रहते हैं जिससे आने-जाने वाले वाहनों को घंटों जाम में रहना पड़ता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वाहनों के सुचारु आवागमन हेतु फोरलेन सड़क से बड़े मालवाहकों को हटाने की कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

योजना बनाने पर विचार

*32 श्री दिलीप राय (सीतामढ़ी स्थानीय प्राधिकार):

Will the गृह be pleased to state:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी थाने को अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित करने की योजना बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ;

(ख) क्या यह सही है कि इसके अभाव में अबतक ऑनलाइन एफ.आई.आर. दर्ज करने का औसत पूरे देश में सबसे कम है ;

(ग) क्या यह सही है कि मॉडर्न तकनीक से लैस होने के बाद पुलिस को कार्य करने में सुविधा होगी जिसका असर अपराध नियंत्रण पर पड़ेगा ;

(घ) क्या यह सही है कि पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण से राज्य की जनता को सहूलियत होगी ;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी थानों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने हेतु योजना तैयार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?
